कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा मई, 2022 माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

I. प्रशिक्षण और क्षमता विकास

i. सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान (आईएसटीएम) ने माह मई 2022 के दौरान 03 संगठन विशिष्ट कार्यक्रम, 07 कैलेंडर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 07 सीएसएस संवर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम और 03 सीएसएसएस संवर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 793 उम्मीदवारों ने भाग लिया ।

ii. विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) ने सूचित किया है कि पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता वृद्धि परियोजना (राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी)- मिशन कर्मयोगी) के लिए 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है।

iii. क्षमता विकास आयोग (सीबीसी) ने निम्नानुसार सूचित किया है: -

(क) सीटीआई को उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में विकसित करने में सहायता के लिए भूमिका आधारित प्रशिक्षण आवश्यकताओं और एक लचीली शासन संरचना प्रदान करने के लिए अधिक वित्तीय और कार्यात्मक स्वायत्तता सहित केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के लिए वैकल्पिक शासन संरचनाओं पर एनएडीटी, नागपुर में एक कार्यशाला का आयोजन।

(ख) अपने संबंधित मंत्रालयों के लिए वार्षिक क्षमता विकास योजनाएं (एसीबीपी) तैयार करने और इसे पूरा करने की समय-सीमा पर चर्चा करने के लिए सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालयों (जनजातीय मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा, महिला और बाल विकास, पंचायती राज) के अपर सचिवों, संयुक्त सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों हेतु दिनांक 31 मई, 2022 को कार्यशाला का आयोजन।

(ग) गोवा राज्य में संस्थागत सुधारों के क्षमता विकास और परिवर्तनकारी विकास प्रक्रिया के संबंध में गोवा राज्य में 19 मई 2022 को कार्यशाला का आयोजन। गोवा के माननीय मुख्यमंत्री इस अवसर पर पधारे जिसमें गोवा सरकार के सभी सचिव और विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।

(घ) इसरो के दो केन्द्रों नामतः त्रिवेंद्रम और अहमदाबाद में प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पहचान करने हेतु क्षमता विकास कार्यशाला आयोजित करने के लिए इसरो के सभी (18) केंद्रों के मानव संसाधन विकास केंद्र प्रमुखों के साथ बैठक।

(ङ) सीबीसी के सदस्यों ने विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों नामतः चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार, पुडुचेरी के लिए पुलिस कर्मयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत अग्रणी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के विभिन्न बैचों में भाग लिया।

(च) माह मई 2022 के दौरान आईआईएम रायपुर, आईआईएम विशाखापत्तनम और भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलोर के साथ ज्ञान साझाकरण (नॉलेज पार्टनरशिप)।

iv. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.05.2022 के का.ज्ञा. के माध्यम से सभी मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को ई-एचआरएमएस प्लेटफॉर्म पर शामिल करने के लिए समेकित दिशानिर्देशों वाला एक मुख्य परिपत्र जारी किया गया।

II. चयन और नियुक्तियां

(i) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश, दिनांक 28.01.2022 और परिणामस्वरूप दिनांक 12.04.2022 के स्थापना (आरक्षण) के निर्देश के आधार पर निम्नलिखित ग्रेडों में पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ की गई है:

(क) यू.एस.एस.एल. 2004-2005 के लिए डीपीसी की समीक्षा हेतु प्रस्ताव यूपीएससी को भेज दिया गया है।

(ख) यू.एस.एस.एल. 2015-2019 के लिए डीपीसी हेतु प्रस्ताव यूपीएससी को भेज दिया गया है।

(ग) वर्ष 2018-2020 के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में समावेश हेतु विचार करने के लिए क्षेत्र (जोन) जारी कर दिया।

(घ) वर्ष 2018 के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में 346 सहायक अनुभाग अधिकारियों को शामिल किया गया है।

(ii) भर्ती वर्ष 2013 के लिए सीधी भर्ती वाले सहायक अनुभाग अधिकारियों (एएसओ) की परस्पर वरिष्ठता का संशोधित मसौदा दिनांक 23.05.2022 को जारी कर दिया गया है।

(iii) दिनांक 11.07.2022 से 07.10.2022 तक 2020 बैच के आईएएस अधिकारियों की सहायक सचिव के रूप में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए सीएसएस के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड के 180 पदों को अस्थायी रूप से बाहर रखा गया था।

(iv) राष्ट्रपति ने न्यायाधीश श्री प्रदीप कुमार मोहन्ती, सदस्य (न्यायिक) को अध्यक्ष, लोकपाल के रूप में कार्य करने को अधिकृत किया है।

(v) पीईएसबी, डीओपीटी ने निदेशक के 07 (सात) पदों और मुख्य प्रबंध निदेशक (सीएमडी)/प्रबंध निदेशक (एमडी) के 02 (दो) पदों के लिए विज्ञापन जारी किए थे। सीएमडी के पद हेतु 01 (एक) चयन बैठक का आयोजन किया गया और निदेशक के पद के लिए 09 (नौ) चयन बैठकों का आयोजन किया गया।

III. आरक्षण मामले

i. बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए दिनांक 17.05.2022 को पदोन्नति में आरक्षण संबंधी विस्तृत एवं समेकित निर्देश जारी किए गए थे।

ii. केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को जांचकर सूची बनाने (टेक स्टॉक लेने) के लिए और उन रिक्तियों को भरने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराने के लिए दिनांक 31.05.2022 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें आरक्षण मामलों को डील करने वाले वरिष्ठ अधिकारी और 10 प्रमुख मंत्रालयों/विभागों, जहां 90% से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, के संपर्क अधिकारियों ने भाग लिया। अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित मंत्रालय/विभाग में आरक्षण नीति को उचित रूप से लागू करने के लिए संपर्क अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदम, बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों के अस्तित्व के कारण, बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को भरने में उनके द्वारा सामना की गई कठिनाइयों तथा अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए इन बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए कार्य योजना पर प्रस्तुतीकरण किया गया।

IV. सेवा मामले

i. दिनांक 13.05.2022 को माननीय राज्य मंत्री (कार्मिक) द्वारा आईएएस अधिकारियों के लिए ई-सिविल सूची, 2022 का आरंभ किया गया है। ई-सिविल सूची 2022 में दिनांक 01.01.2022 तक आईएएस अधिकारियों के विवरण अर्थात संवर्ग, तैनाती, योग्यता इत्यादि से संबंधित डाटा शामिल है और अब यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट https://dopt.gov.in पर उपलब्ध है।

ii. कर्नाटक के राज्य सिविल सेवाओं/गैर-राज्य सिविल सेवाओं से 3, छत्तीसगढ़ से 7, मिजोरम से 2 कुल 12 आईएएस अधिकारियों की पदोन्नति/चयन द्वारा नियुक्तियों को मई, 2022 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था।

iii. तीन आईएएस अधिकारियों के संबंध में संवर्ग बदलने के लिए अधिसूचनाएं जारी की गई।

iv. राज्य सिविल सेवाओं (09)/गैर-राज्य सिविल सेवाओं (01), त्रिपुरा से श्रेणी (04), तमिलनाडु (05) और झारखंड (01) से आईएएस में नियुक्त 10 आईएएस अधिकारियों को वरिष्ठता/आवंटन के वर्ष के निर्धारण हेतु आदेश जारी किए गए।

V. सतर्कता मामले

i. जेएस मनोनयन (एम्पैनलमेंट) के लिए 53 (तिरपन) आईएएस अधिकारियों को सतर्कता मंजूरी जारी की गई।

ii. एएस मनोनयन (एम्पैनलमेंट) के लिए 11 (ग्यारह) अधिकारियों को सतर्कता मंजूरी जारी की गई।

iii. विभिन्न उद्देश्यों अर्थात् अंतर-संवर्ग प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, परिवीक्षा इत्यादि के लिए 96 (छियानवे) आईएएस अधिकारियों को सतर्कता मंजूरी जारी की गई।

VI. स्थापना मामले

दिनांक 20.05.2022 के का.ज्ञा.सं. 12/1/2022-जेसीए के तहत ओडिशा, केरल और उत्तराखंड के 03 (तीन) विधान सभा क्षेत्रों के लिए उप चुनाव के दौरान दिनांक 31.05.2022 को मतदान दिवस को कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश की मंजूरी के संबंध में निर्देश जारी किया गया था।

VII. विशेष अभियान

मई, 2022 के दौरान, 297 के बैकलॉग सहित 1098 लोक शिकायतों में से 646 लोक शिकायतों का निवारण किया गया था. रिकॉर्ड प्रबंधन के हिस्से के रूप में 3009 फाइलों की समीक्षा की गई और 2026 फाइलों की छंटनी की गई तथा 07 अंतर मंत्रालयी कैबिनेट के संदर्भों का निपटान किया गया।